

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

10 फाल्गुन, 1940 (श॰)

संख्या- 173 राँची, श्क्रवार, 1 मार्च, 2019 (ई॰)

नगर विकास एवं आवास विभाग (आवास विभाग)

संकल्प

28 फ़रवरी. 2019

विषय:- झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के द्वारा दायर सर्टिफिकेट वाद संख्या 02/HB/2006-07 के अन्सार राँची विश्वविद्यालय द्वारा शेष भ्गतेय राशि 19,64,98,466.00/- रूपया Waive करने के संबंध में।

संख्या-**७/न॰वि॰आ॰/विधि-१८/२०१७-९७१**--बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना के पत्रांक-४७२२ दिनांक-05.07.1976 द्वारा राँची विश्वविद्यालय के कर्मियों हेत् बरियात् स्थित 192 अल्प आय वर्गीय फ्लैटों का आवंटन प्रति फ्लैट 22,000/- (बाईस हजार) रूपये की दर से 42,24,000/- (बेयालिस लाख चौबीस हजार) रूपये निर्धारित किया गया, जिसका एकारनामा दिनांक-05.07.1976 एवं 22.07.1976 को किया गया। एकरारनामा के अनुसार 7 तारीख तक 31,795.00 एवं 7 तारीख के बाद 36,014.00 रूपया क्रमशः 8.5% एवं 11% चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 180 मासिक किस्तों में भ्गतान किया जाना था। राँची विश्वविद्यालय द्वारा समय पर भुगतान नहीं होने के कारण ब्याज की राशि में कालान्तर वृद्धि होती गई।

- 2. समयानुसार किस्तों का भुगतान नहीं किये जाने के कारण सर्टिफिकेट वाद नं॰ 02 एच॰बी॰/2006-07 दायर किया गया है जो अबतक विचाराधीन है।
- 3. राँची विश्वविद्यालय, राँची को आवंटित फ्लैटों के विरूद्ध अबतक भुगतान किये गये कुल राशि 9,08,86,264/- रू॰ को समायोजन के पश्चात् अद्यतन गणना प्रपत्र के अनुसार दिनांक-31.10.2018 तक मात्र 19,64,98,466.00/- रूपया बोर्ड को देय होता है।
- 4. माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड की अध्यक्षता में दिनांक 13.07.2018 की समीक्षात्मक बैठक की कंडिका संख्या 18 में निदेश दिया गया कि राँची विश्वविद्यालय जितनी राशि स्वंय दे सकेगा उतनी राशि प्राप्त कर शेष राशि को Weive करने हेतु मंत्री परिषद् के समक्ष उपस्थापित किया जाय।
- 5. उक्त के आलोक में राँची विश्वविद्यालय, राँची द्वारा झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड राँची को देय शेष भुगतेय राशि 19,64,98,466.00/- (उनीस करोड़ चौंसठ लाख अन्ठान्बे हजार चार सौ छियासठ) रूपये को Weive किया जाता है।
- 6. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति नगर विकास एवं आवास विभाग के संलेख ज्ञापांक 817 दिनांक 21.02.2019 के क्रम में दिनांक 21.02.2019 की बैठक के मद संख्या 19 में दी गई है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अजय कुमार सिंह, सरकार के सचिव।